राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल द्वितीय अपील संख्या 104/1988

1. राधेश्याम पुत्र श्री कन्हैयालाल

2. ओम प्रकाश (मृत होने के बाद)

2/1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश

2/2. दीपक पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश

2/3. कमलेश पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश

2/4. ज्योति पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश

सभी निवासीयान खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर

3. गजानंद पुत्र श्री शीशपाल (अब मृतक)

3/1. श्रीमती मगन देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री गजानंद

3/2. हरि शंकर

3/3. भवानी शंकर

3/4. वासुदेव

3/5. राज कुमार

स्वर्गीय श्री गजानंद के सभी पुत्र

4. देवी दत्त पुत्र श्री लादूराम (अब मृतक)-

4/1. श्रीमती जादव देवी पत्नी स्वर्गीय श्री देवी दत्त

4/2. श्री सुशील कुमार शर्मा (अब तक मृतक)

4/2/1 श्रीमती राधा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सुशील कुमार

4/2/2 श्री महेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री सुशील कुमार

4/2/3 श्री दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री सुशील कुमार

4/2/4 मधु देवी पुत्री स्वर्गीय श्री सुशील कुमार

4/3 श्री सुनील कुमार शर्मा

4/4. श्री अनिल कुमार शर्मा स्वर्गीय श्री देवी दत्त के सभी पुत्र

4/5. श्रीमती पुष्पा देवी

4/6. श्रीमती बनारसी देवी

4/7. श्रीमती ललिता देवी

4/8. श्रीमती नीता देवी

श्री देवी दत्त की सभी पुत्रियाँ और खाटूश्यामजी, तहसील दंतारामगढ़, जिला सीकर के सभी निवासी।

5. गोविंद राम (मृतक)

5/1. मदनलाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री गोविंद राम निवासी खाटूश्यामजी, तहसील दंतारामगढ़, जिला सीकर।

6. खुदा बक्स पुत्र श्री नबाब तेली मृतक के बाद से (कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के रूप में अभिवादित)

सभी निवासी खाटूश्यामजी, तहसील दंतारामगढ़, जिला सीकर।

7. राधेश्याम पुत्र श्री बनवारीलाल शर्मा (अब मृतक)

7/1. श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राधेश्याम

7/2. नरेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राधेश्याम

सभी निवासी खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री केशर देव (अब मृतक)-

1/1. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री केशर देव

1/2. राजेंद्र कुमार शर्मा

1/3. सोहनलाल शर्मा

1/4. गोरधनलाल शर्मा

1/5. श्रवण कुमार शर्मा

स्वर्गीय श्री केशर देव के सभी पुत्र, खाटूश्यामजी के निवासी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

1/6. श्रीमती हेम लता पत्नी श्री चितरंजन लाल शर्मा, निवासी ग्राम एवं कीट- हाशपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर

1/7. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री शरत कुमार जोशी निवासी छावनी बाजार झुंझुनू, जिला झुंझुनू

2. गोविन्द राम पुत्र श्री सोजी राम जाट

3. सत्यनारायण पुत्र श्री सांवर राम शर्मा

4. दीपू राम पुत्र श्री खेमाराम जाट

दोनों प्रतिवादियों, सत्यनारायण और दीपाराम के नाम हटा दिए गए।

5. झुंथा राम (अब मृतक) पुत्र श्री गाडू राम मीना

5/1. श्रीमती सकारी पुत्री स्वर्गीय श्री झुंथा राम

5/2. श्री राम स्वरूप दत्तक पुत्र श्री झुंथा राम

समस्त निवासी खाटूश्यामजी, तह. दांतारामगढ, जिला सीकर

6. माली राम पुत्र गाडू राम मीना (अब मृतक)

6/1 श्री रामरतन

6/2 श्री बाबूलाल (मृतक)

6/2/1 मृतक बाबू लाल की मां शांति देवी, जैसा कि पहले से ही प्रतिवादी संख्या 6/6 के रूप में दर्ज है।

7. श्रीमती अचुकी तेली पत्नी स्वर्गीय श्री खुदा बक्स

8. श्री हजारी खा तेली पुत्र स्वर्गीय श्री खुदा बक्स

9. श्री बाबू खा तेली पुत्र स्वर्गीय श्री खुदा बक्स

सभी निवासी मकान नं. 95, मौहल्ला तेलियान, मेमावत वाली गली, खाटू श्यामजी, जिला सीकर

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.पी. गोयल वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई सुश्री ज्योति स्वामी, श्री आर.पी अग्रवाल

प्रत्यार्थी की ओर से : श्री एम.एम. रंजन सीनियर एडवोकेट, श्री दौलत शर्मा एवं श्री हेमेन्द्र शर्मा ने सहयोग किया

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

निर्णय

आरक्षित करने की तारीख : 01/09/2022

उच्चारित करने की तारीख : 11/10/2022

रिपोर्टेबल

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत तत्काल दूसरी अपील केशर देव एवं अन्य बनाम राधेश्याम एवं अन्य शीर्षक वाली स्थायी निषेधाज्ञा संख्या 39/1976 (198/1980) के लिए एक सिविल सूट से उत्पन्न होती है जिसे मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़, जिला सीकर ने दिनांक 21.12.1981 के निर्णय और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया था, लेकिन न्यायालय के समक्ष नंबर 7/1982 (33/1985) के खिलाफ सिविल प्रथम अपील दायर करने पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीकर के निर्णय और डिक्री दिनांक 13.05.1988 द्वारा इसकी अनुमति दी गई है और इसके तहत दिनांक 21.12.1981 के निर्णय और डिक्री को रद्द करते हुए, उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर सिविल सूट को निम्नलिखित शर्तों में

डिक्री किया गया है:-

> "उक्त विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थीगण की अपील विरुद्ध प्रत्यार्थीगण-प्रतिवादीगण मय दोनों न्यायालय का खर्चा के स्वीकार की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय का चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक २१.१२.१९८१ अपास्त किया जाता है एवं वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण -प्रत्यार्थी स्थायी निषेधाज्ञा हेतु इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आम रास्ता की भूमि जो वाद के सलग्न मानचित्र में लाल रंग से अंकित किया गया है, पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे तथा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे न ही कोई आवागमन में बाधा डालें, सार्वजनिक चौक व रास्ता को खुला रखें।"

2. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 23.03.1993 के आदेश के तहत इस दूसरी अपील में विचार के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं:

> "क्या विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ताओं को बेची गई भूमि गांव के सार्वजनिक रास्ते/चौक का हिस्सा थी, विकृत है"?"

3. कानून के उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए, वर्तमान मामले के रिकॉर्ड से निकाले गए मौलिक तथ्यों पर निम्नानुसार ध्यान देना आवश्यक है:

3.1. प्रारंभ में, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा 06.04.1976 को सात प्रतिवादियों (अपीलकर्ता संख्या 1 से 7) के खिलाफ चार व्यक्तियों (यहाँ प्रतिवादी संख्या 1 से 4) द्वारा दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हुए कहा गया था कि ग्राम खाटूश्यामजी में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए एक सार्वजनिक धर्मशाला है। धर्मशाला के सामने एक सार्वजनिक रास्ता

और चौक है, जिसकी चौड़ाई लगभग 55 फीट है और उसके बाद विपरीत दिशा में झुंथा राम और माली राम की ग्वारियां और बाड़े स्थित हैं और उसके बगल में अन्य व्यक्तियों की ग्वारियां भी स्थित हैं तथा गुआरियों और बड़ों द्वार सार्वजनिक रास्ते की ओर खुले हैं। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक धर्मशाला तथा जुंथा राम और माली राम और अन्य व्यक्तियों की ग्वारियों व बाड़ों के बीच में गांव का सार्वजनिक रास्ता है। यह कहा गया था कि प्रतिवादी, ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी के साथ मिलकर सार्वजनिक रास्ते और चौक की भूमि पर अवैध और अनधिकृत निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और यदि ऐसे निर्माणों को करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे सार्वजनिक परिवहन बाधित होगा और जनता के आवागमन का रास्ता सीमित हो जाएगा। अतः वादीगणों ने संयुक्त रूप से प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा, सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर बाधा न डालने तथा खाटू रींगस से खाटू दांतारामगढ़ तक, जो मुख्य सड़क है, के सार्वजनिक रास्ते के किसी भी भाग पर कोई निर्माण न करने देने की प्रार्थना की।

3.2. सिविल सूट की दायर करने के बाद, दो व्यक्ति झुंथा राम और माली राम भी वादी नंबर 5 और 6 और ग्राम के रूप में शामिल हुए और साथ ही पंचायत, खाटूश्यामजी को भी प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में जोड़ा गया और तदनुसार, 17.01.1977 को संशोधित वाद दायर किया गया।

3.3. इसके बाद, इस आशय का पैरा संख्या 4(क) जोड़कर वादपत्र में संशोधन किया गया कि ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी ने सार्वजनिक रास्ते का कुछ हिस्सा अलग-अलग भूखंडों के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को अनुचित, अनधिकृत और अवैध तरीके से बेचा और उनके पक्ष में अलग-अलग सात विक्रय पत्र/पट्टे निष्पादित किए। ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी, सार्वजनिक रास्ते को निर्बाध रखने के लिए बाध्य है और वह सार्वजनिक रास्ते की भूमि को बेचने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख या पट्टे शुरू से ही शून्य और अप्रभावी हैं और ऐसे विक्रय पत्रों/पट्टों के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 7 तक ने सार्वजनिक मार्ग की भूमि पर कोई अधिकार अर्जित नहीं किया।

<u>टिप्पणी:</u> यहां यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि वादपत्र में संशोधन की मांग करते समय, ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी के ऐसे सात बिक्री कार्यों/पट्टों को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पक्ष में अवैध, शून्य और बातिल घोषित करने की मांग के लिए कोई प्रार्थना शामिल नहीं की गई थी। (यहाँ इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि फैसले के उत्तरार्ध में तथ्यों और साक्ष्यों की चर्चा के बाद, यह पता चलता है कि वादी संख्या 5 और 6 के आदेश पर प्रतिवादियों के पट्टों को दी गई चुनौती अतिरिक्त कलेक्टर, सीकर के न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.03.1976 के तहत पहले ही विफल हो चुकी है और जिला कलेक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 20.04.1976 के माध्यम से यह पाया गया कि सभी विक्रय विलेख/पट्टे उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से जारी किए गए थे जो कानूनी और वैध थे, इसलिए, इन बिक्री कार्यों/पट्टों को अमान्य घोषित करने की प्रार्थना 13.11.1981 को संशोधित वाद दायर करने की तारीख पर तीन साल की सीमा के कारण वर्जित हो गई है। इसलिए, अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय के समक्ष अपनी विफलता को छिपाते हुए और सिविल न्यायालय के समक्ष पट्टों को चुनौती देते हुए, सिविल न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल मुकदमा दायर करने के संबंध में इन विक्रय विलेखों/पट्टों को अमान्य घोषित करने की तीन वर्ष की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद, वादी वास्तविक नहीं हैं।)

3.4. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 7 तक ने अपने संयुक्त एवं अलग-अलग लिखित बयान में तर्क दिया कि धर्मशाला के सामने 20 फीट खुली जगह छोड़कर 30 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता है तथा उसके बाद प्रश्नगत भूमि है, जिसे बेच दिया गया है। प्रतिवादियों के लिए ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी स्थित है और फिर उसके दक्षिण की ओर झुंथा राम का बाड़ा स्थित है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है, इसी प्रकार माली राम का ग्वारी उसके बाद स्थित है और जिसका मुख दक्षिणकी ओर है। इस बात से साफ इनकार कर दिया गया कि झुंथा राम और माली राम के ग्वारियों और बाड़ों के दरवाजे खाटू रींगस की मुख्य सार्वजनिक सड़क पर उत्तरी दिशा की ओर खुलते हैं। प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि ग्राम

पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा उन्हें सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेची गई भूमि और जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा उनके पक्ष में पट्टे जारी किए गए हैं, वह सार्वजनिक रास्ते की भूमि नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को आवंटित विचाराधीन भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि से पूरी तरह से अलग है और सार्वजनिक रास्ते के दक्षिणी ओर स्थित है। प्रतिवादियों ने उनकी भूमि ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी से नीलामी में खरीद कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा उनकी खरीदी गई भूमि पर दुकानों का निर्माण कर 30 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते को यथावत रखा हुआ है। वादीगण ने मनगढ़ंत कहानी रचकर पूर्णतः झूठा मामला बनाया है कि सार्वजनिक रास्ते की भूमि का कुछ भाग प्रतिवादियों को बेच दिया गया है, अतः स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दीवानी वाद खारिज किये जाने योग्य है।

यह भी तर्क दिया गया कि वादी संख्या 5-झुंथा राम और वादी संख्या 6-माली राम ने अतिरिक्त कलेक्टर/जिला कलेक्टर, सीकर के न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर करके प्रतिवादियों के पट्टों को चुनौती दी। वादी क्रमांक 5 झुंटा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को आदेश दिनांक 12.03.1976 द्वारा प्रतिवादियों के पट्टों को वैध मानते हुए वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया है। वादी संख्या 6-माली राम द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को आदेश दिनांक 20.04.1976 द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया है और प्रतिवादियों के पट्टे कानून के अनुसार जारी किए गए पाए गए हैं। वास्तव में, वादी संख्या 5 और 6 के पास पश्चिम की ओर से अपने गुआरियों और बाड़ों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार हैं और प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को आवंटित भूमि की ओर कोई प्रवेश/द्वार नहीं है। यह कहा गया था कि वादी संख्या 1 से 4 के पास कोई प्रवेश द्वार नहीं है। प्रतिवादियों को बेची गई भूमि के पास घर या भूमि और वर्तमान सिविल मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने वर्तमान सिविल वाद दुर्भावनापूर्ण ढंग से किसी गुप्त उद्देश्य से दाखिल किया है, जो जुर्माने के साथ खारिज किया जा सकता है।

3.5. यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रायल कोर्ट के विद्वान पीठासीन अधिकारी ने

स्वयं विवादित स्थल का दो बार दौरा किया। मानचित्र के साथ प्रथम स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 29.05.1976 (अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 22/1976 की फ़ाइल में) में नोट की गई है और दूसरे पीठासीन अधिकारी की दूसरी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, दिनांक 09.11.1980, मूल सिविल वाद की फाइल में भी उपलब्ध है। दोनों स्थल निरीक्षण रिपोर्टों में, खाटू रींगस रोड की मुख्य सार्वजनिक सड़क, जिसकी चौड़ाई 30 फीट है, साइट पर उपलब्ध पाई गई और प्रतिवादियों को आवंटित भूमि, सार्वजनिक सड़क से अलग है और 30 फीट चौड़ाई छोड़कर दक्षिणी तरफ स्थित सड़क बरकरार है।

3.6. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने, मुद्दों को तैयार करने और दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, वादी के खिलाफ मुद्दे संख्या 1 और 3 का फैसला किया और दोनों पक्षों के पूरे साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद, पीठासीन अधिकारी की साइट निरीक्षण रिपोर्ट के साथ, तथ्य के निष्कर्ष दर्ज किए गए कि ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 7 को आवंटित प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा नहीं है और इसके अलावा 30 फीट चौड़ा सार्वजनिक मार्ग साइट पर उपलब्ध है, जो प्रश्नगत भूमि के इस तरह के आवंटन से अप्रभावित रहता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादियों को बेची गई प्रश्नगत भूमि (पट्टा पूर्व-ए1 से ए7 के माध्यम से) सार्वजनिक रास्ते के दक्षिणी ओर स्थित है और वह भूमि न तो सार्वजनिक रास्ते का हिस्सा है और न ही ऐसा आवंटन किसी भी तरह से सार्वजनिक रास्ते को बाधित करती है। ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि वादी धर्मशाला के सामने सार्वजनिक रास्ते/चौक की चौड़ाई 55 फीट साबित करने में बुरी तरह विफल रहे और चूंकि प्रतिवादियों को आवंटित भूमि न तो किसी सार्वजनिक रास्ते का हिस्सा है और न ही किसी चौक का, इसलिए प्रतिवादियों को आवंटित भूमि के संबंध में वादी का कोई स्टैंडी/अधिकार नहीं है। यह देखा गया कि वादी संख्या 5-झुंथा राम और वादी संख्या 6-माली राम ने झूठ कहा है कि यदि प्रतिवादियों को उन्हें आवंटित भूमि पर निर्माण करने की अनुमति दी जाती है, तो उनके ग्वारिस और बडा के द्वार/प्रवेश में बाधा उत्पन्न होगी। झुंथा राम और माली राम की गुआरियों का प्रवेश पश्चिमी तरफ से है, न कि उत्तरी

तरफ की भूमि से होकर। ऐसे तथ्य निष्कर्षों के साथ, ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 21.12.1981 के निर्णय और डिक्री द्वारा वादी के मुकदमे को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया।

3.7. प्रथम अपील दायर करने पर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीकर ने दिनांक 13.05.1988 को आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा स्वयं की टिप्पणियों और तर्कों से ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष और फैसले को पलट दिया और वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया। प्रथम अपीलीय अदालत ने दिनांक 13.05.1988 के फैसले और डिक्री द्वारा, ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक अपीलकर्ताओं को आवंटित प्रश्नगत भूमि को सार्वजनिक रास्ते का हिस्सा माना है और इस प्रकार प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे ऐसा कोई भी निर्माण न करें और सार्वजनिक रास्ते पर कोई अतिक्रमण न करें, साथ ही सार्वजनिक रास्ते पर आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न न करें और सार्वजनिक रास्ते और चौक को खुला रखें। प्रथम अपीलीय अदालत के दिनांक 13.05.1988 के इस फैसले और डिक्री को प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं ने तत्काल दूसरी अपील दायर करके चुनौती दी है।

4. विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री जे.पी. गोयल, प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय अदालत ने ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादियों को आवंटित भूमि को सार्वजनिक भूमि का हिस्सा मानने और इस प्रकार का निर्देश देने कि प्रतिवादीगण उन्हें आवंटित भूमि पर निर्माण न करें, गंभीर विकृति की है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवादियों को आवंटित भूमि सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा नहीं है, बल्कि 30 फीट चौड़ा सार्वजनिक मार्ग बरकरार है और साइट पर उपलब्ध है। प्रतिवादियों को आवंटित भूमि 30 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता छोड़कर दक्षिणी दिशा में स्थित है और प्रतिवादियों को आवंटित भूमि न तो सार्वजनिक रास्ते को बाधित करती है और न ही सार्वजनिक रास्ते पर आवाजाही को बाधित करती है। प्रथम अपीलीय अदालत ने धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होकर ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड और

निष्कर्षों के विपरीत एक गलत धारणा बनाई है। अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील-प्रतिवादियों ने कहा कि मूल रूप से वादी ने इसकी स्थापना की स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रतिवादी धर्मशाला के सामने सार्वजनिक रास्ते और चौक की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने के इच्छुक हैं। जबकि रिकॉर्ड में आया है कि धर्मशाला के सामने सार्वजनिक सड़क की चौड़ाई 30 फीट है, वह भी धर्मशाला के सामने 20 फीट चौड़ी खुली जगह छोड़कर, धर्मशाला के सामने स्थित 20 फीट खुली पंचायत से धर्मशाला तक की जगह ग्राम द्वारा पहले ही आवंटित की जा चुकी है। वादी पक्ष का मामला है कि धर्मशाला के सामने सार्वजनिक सड़क व चौक की चौड़ाई 55 फीट है, यह किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं हुआ है तथा प्रतिवादियों को आवंटित भूमि धर्मशाला के सामने 20 फीट चौड़ी खुली जगह छोड़कर, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 30 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता छोड़कर स्थित है। इसके अलावा, प्रतिवादियों को प्रश्नगत भूमि के आवंटन से, वादी संख्या 5 और 6 झुंथा राम और माली राम के ग्वारियों और बाड़ों के प्रवेश द्वार में भी किसी भी तरह से बाधा नहीं आती है, क्योंकि उनके ग्वारियों और बाड़ों के द्वार/प्रवेश द्वार पश्चिमी दिशा से हैं और वादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादियों के पट्टों को दी गई चुनौती को पहले ही वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया है और वादी संख्या 6 द्वारा दी गई चुनौती को गुण-दोष के आधार पर पहले ही खारिज कर दिया गया है, जिसमें प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं को पट्टे जारी करने को वैध और नियमों के अनुरूप माना गया है, इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल सूट को सही ढंग से खारिज कर दिया, जिसे मुख्य रूप से केवल वादी नंबर 5 और 6 द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया गया था। है। लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के तथ्यान्वेषण और डिक्री को उलटने में विकृति और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है और एक गलत धारणा और बहाने के तहत वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाया है। अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के अनुसार, पहले के अवलोकन और निष्कर्ष ग्राम द्वारा बेची/आवंटित भूमि पर विचार करने हेतु अपीलीय न्यायालय प्रतिवादियों के लिए पंचायत, खाटूश्यामजी सार्वजनिक रास्ते/चौक का हिस्सा है, पूरी तरह से विकृत है और बिना किसी

सबूत पर आधारित है, ऐसे में प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 13.05.1988 कानून की नजर में अस्थिर है और उत्तरदायी है रद्द कर दिया गया, ताकि ट्रायल कोर्ट के दिनांक 21.12.1981 के फैसले और डिक्री को बहाल किया जा सके, जिसमें उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल सूट को खारिज करने की पुष्टि की गई थी।

5. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री एम.एम. रंजन, प्रतिवादियों-वादीगणों की ओर से उपस्थित होकर, दिनांक 13.05.1988 के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह कहा है कि प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्ष किसी भी तरह से विकृत नहीं हैं, इसलिए धारा 100 सीपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, तत्काल दूसरी अपील खारिज होने योग्य है।

6. यह न्यायालय, सबसे पहले धारा 100 सीपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय के दायरे और अधिकार क्षेत्र पर विचार करना चाहेगा, ताकि ट्रायल कोर्ट के तथ्य निष्कर्षों के उलट होने के बाद पहली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके।

7. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा है, यह एक अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि 1976 के संशोधन के बाद धारा 100 सीपीसी के तहत दूसरी अपील पर विचार करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल तभी सीमित है जब दूसरी अपील में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हों। धारा 100 सीपीसी के तहत उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए "कानून के पर्याप्त प्रश्न" का अस्तित्व अनिवार्य है। जबकि उच्च न्यायालय धारा 100 सीपीसी के तहत दूसरी अपील का निर्णय नहीं कर सकता और नहीं प्रथम अपीलीय अदालत की तरह कार्य नहीं करना चाहिए और निचली अदालतों के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संपूर्ण साक्ष्यों की दोबारा समीक्षा की अनुमति नहीं है, जब तक कि निचली अदालत का निष्कर्ष विकृत न हो और कानून के स्थापित प्रस्ताव के विपरीत न हो।

8. माननीय ***गुरनाम सिंह बनाम लेहना सिंह [(2019) 7 एससीसी 641]*** के

मामले में एक हालिया फैसले में उच्चतम न्यायालय ने ***कोंडीबा दगडु कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर*** [***(1999) 3 एससीसी 722***] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक प्रसिद्ध फैसले पर भरोसा करते हुए यह निर्णय दिया था: "धारा 100 सीपीसी के तहत एक दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय पहली अपीलीय अदालत के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, जब तक कि वह यह नहीं पाता कि निचली अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निम्न कारणों से ग़लत थे :

(i) लागू कानून के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत थे;

अथवा

(ii) सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई विधिक उद्घोषणाओं के विपरीत थे;

अथवा

(iii) अस्वीकार्य साक्ष्य या बिना साक्ष्य पर आधारित थे।

कोंडीबा दगडु कदम (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि यदि प्रथम अपीलीय अदालत ने न्यायिक तरीके से अपने विवेक का प्रयोग किया है, तो उसके निर्णय को विधि की या द्वितीय अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली प्रक्रिया में किसी त्रुटि से युक्त के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है। आगे यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट अलग तरीके से निर्णय ले सकता था, यह दूसरी अपील में हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाली विधि का सवाल नहीं है।

9. ***संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम तिवारी [(2001) 3 एससीसी 179] के मामले में*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलटने या उनकी पुष्टि करने के लिए प्रथम अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा की। यह देखा गया कि प्रथम अपील पक्षकारों का एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक कि यह कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो, पूरा मामला तथ्य और कानून दोनों के सवालों पर दोबारा सुनवाई के लिए खुला है। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए यह माना गया कि प्रथम अपीलीय अदालत का कार्य आसान है, क्योंकि

उस स्थिति में, जब पहली अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट के तथ्यों से सहमत होती है, तो उसे प्रभाव को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। साक्ष्य का या ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारणों को दोहराना और ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारणों के साथ प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा सामान्य सहमति की अभिव्यक्ति, आमतौर पर पर्याप्त होगी, लेकिन उलटफेर का निर्णय लिखते समय, प्रथम अपीलीय अदालत को इसके दो सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना चाहिए। सबसे पहले, ट्रायल कोर्ट द्वारा प्राप्त विरोधाभासी सबूतों पर आधारित तथ्य के निष्कर्षों को अपीलीय अदालत के साथ तौला जाना चाहिए, खासकर तब जब निष्कर्ष उसी पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए मौखिक साक्ष्य पर आधारित हों जो निर्णय लिखता है। दूसरे, किसी तथ्य के निष्कर्ष को उलटते समय अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क के करीब आना चाहिए और फिर अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपना तर्क देना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रथम अपीलीय अदालत, पहले की तरह, तथ्य की अंतिम अदालत बनी हुई है, हालाँकि, प्रथम अपीलीय अदालतें अतिरिक्त दायित्व के तहत हैं, और ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलटते समय, इसे ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क पर विवेक का सचेत अनुप्रयोग करना चाहिए और फिर विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के तर्क को निर्दिष्ट करना ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलटते हुए, संहिता में प्रतिस्थापित वर्तमान धारा 100 की योजना के तहत प्रथम अपीलीय अदालत पर डाला गया यह अतिरिक्त दायित्व आगे की गई अपील की सुनवाई करते हुए अदालत को इस संबंध में संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है कि प्रथम अपीलीय अदालत ने उससे अपेक्षा के अनुरूप अपना कर्तव्य निभाया है।

10. यहां यह देखा जा सकता है कि प्रथम अपीलीय अदालत पर कर्तव्य/दायित्व डालने के संबंध में **संतोष हजारी** (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का सिद्धांत, विशेष रूप से, तथ्य निष्कर्षों को उलटते हुए ट्रायल कोर्ट में बार-बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनगिनत निर्णयों का पालन किया गया है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि

उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान दूसरी अपील में भी इस निर्णय पर भरोसा किया है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***दामोदर लाल बनाम सोहन देवी [(2016) 3 एससीसी 78]*** के मामले में किराये की संपत्ति में भौतिक परिवर्तन के मुद्दे पर निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों के मामले से निपटने के दौरान और "विकृति" की अवधारणा की जांच करते समय, यह देखा कि नीचे दी गई अदालतों का गलत निष्कर्ष साक्ष्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या से उत्पन्न होना चाहिए या यह केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित होना चाहिए। विकृति पर सबसे सुरक्षित दृष्टिकोण उचित व्यक्ति के तथ्यों पर हस्तक्षेप पर क्लासिक दृष्टिकोण है। उनके लिए, यदि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों और सबूतों पर निष्कर्ष संभव है, तो कोई विकृति नहीं है। यदि नहीं, तो निष्कर्ष विकृत है। साक्ष्य की अपर्याप्तता या साक्ष्य का अलग-अलग अध्ययन विकृति नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ***कुलवंत कौर बनाम गुरदयाल सिंह मान [(2001) 4 एससीसी 262]*** के मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले पर भरोसा जताया, जहां पैरा संख्या 13 में, इसे निम्नानुसार वर्णित किया गया था:

> "34. माना जाता है कि, जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, धारा 100 ने दूसरी अपील में क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर एक निश्चित प्रतिबंध लगाया है। यह रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 ने ऐसे निश्चित उद्देश्यों के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाया था और चूंकि हमें उस संबंध में आगे की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम विवरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि जबकि यह है सच है कि दूसरी अपील में तथ्य का निष्कर्ष, भले ही गलत हो, आम तौर पर प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां यह पाया जाता है कि निष्कर्ष गलत परीक्षण और मान्यताओं और अनुमानों के आधार पर विकृत हैं और परिणामस्वरूप इसमें विकृति का तत्व शामिल है उसमें, हमारे विचार में इस मुद्दे से निपटने के लिए उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। हालाँकि,

यह केवल उस स्थिति में है जब इस तरह के तथ्य को उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकाश में लाया जाता है और न्याय की अवधारणा की तुलना में विकृति के मुद्दे पर निर्णय भी स्पष्ट होना चाहिए। हालाँकि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विकृति अपने आप में निर्णय लेने योग्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न है - विकृति के संबंध में उच्च न्यायालय की ओर से एक स्पष्ट निष्कर्ष की आवश्यकता है। इस संदर्भ में संहिता की धारा 103 का संदर्भ लें जो इस प्रकार है:

> "103. ***तथ्य के मुद्दों को निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति*** - किसी भी दूसरी अपील में, तो उच्च न्यायालय, यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर्याप्त है, अपील के निपटान के लिए आवश्यक किसी भी मुद्दे को निर्धारित कर सकता है –
>
> (क) 'जो निचली अपीलीय अदालत या प्रथम दृष्टया अदालत और निचली अपीलीय अदालत दोनों द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, या
>
> (ख) जिसे कानून के ऐसे प्रश्न पर निर्णय के कारण ऐसी अदालत या अदालतों द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया है जैसा कि धारा 100 में संदर्भित है।'

अपेक्षाएँ धारा 103 में निर्दिष्ट हैं और इससे कम कुछ भी इसे धारा 100 के दायरे में नहीं लाएगा क्योंकि विकृति का मुद्दा भी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के दायरे में आएगा, जैसा कि ऊपर देखा गया है। तथ्य की खोज की वैधता को कानून का प्रश्न कहा जा सकता है। हालाँकि, हम दोहराते हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले में इस आशय का एक निश्चित निष्कर्ष होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संहिता की धारा 100 का अनुपालन किया जाता है।

12. अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने ***सेबस्टियाओ लुइस***

फर्नांडीस बनाम के.वी.पी. शास्त्री [(2013) 15 एससीसी 161] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के समवर्ती निष्कर्षों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की पुष्टि की, जहां तथ्य के निष्कर्ष विकृत हैं और तथ्य की गलत धारणाओं पर आधारित हैं, रिकॉर्ड पर दलीलों और सबूतों का समुचित अवलोकन नहीं किया गया है और उसके साथ-साथ साबित करने के लिए बोझ को गलत तरीके से रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने **हीरा लाल बनाम गज्जन [(1990) 3 एससीसी 285]** में दिए गए फैसले के पैरा 8 के प्रासंगिक हिस्से का हवाला दिया:-

> "8....यदि तथ्य के किसी प्रश्न से निपटने में निचली अपीलीय अदालत ने जिम्मेदारी गलत पक्ष पर डाल दी है और उसके तथ्य का पता लगाना काफी हद तक इस गलत दृष्टिकोण का परिणाम है तो इसे प्रक्रिया में दोष माना जा सकता है। जब प्रथम अपीलीय अदालत ने साक्ष्य को अस्वीकार्य मानकर खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय संतुष्ट हो गया कि साक्ष्य स्वीकार्य था, इससे प्रक्रिया में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ऐसे मामले में भी जहां निचली अदालत ने सबूतों के महत्व को नजरअंदाज कर दिया और निर्णय को अप्रासंगिक मामलों से प्रभावित होने दिया, उच्च न्यायालय के लिए सबूतों का फिर से अवलोकन करना और अपने स्वयं के स्वतंत्र निर्णय पर आना उचित होगा...।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 100 सीपीसी से संबंधित सिद्धांतों को भी दोहराया, जिन्हें ***हीरो विनोथ बनाम शेषम्मल [(2006) 5 एससीसी 545]*** के फैसले के पैरा 24 में संक्षेपित किया गया था, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"24. इस मामले के लिए प्रासंगिक धारा 100 सीपीसी से संबंधित सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) किसी दस्तावेज़ के विवरण या सामग्री से तथ्य का अनुमान तथ्य का प्रश्न है। लेकिन किसी दस्तावेज़ की शर्तों का कानूनी प्रभाव कानून का प्रश्न है। कानून के किसी सिद्धांत के अनुप्रयोग से जुड़े दस्तावेज़ का निर्माण भी कानून का प्रश्न है। इसलिए, जब किसी दस्तावेज़ का गलत निर्माण होता है या किसी दस्तावेज़ की व्याख्या करने में कानून के सिद्धांत का गलत अनुप्रयोग होता है, तो यह कानून के प्रश्न को जन्म देता है।

(ii) उच्च न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मामले में विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, न कि केवल विधि का प्रश्न। विधि का कोई प्रश्न जिसका मामले के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (अर्थात्, ऐसा प्रश्न, जिसका उत्तर मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है) विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यदि वह विधि के विशिष्ट प्रावधान अथवा बाध्यकारी पूर्वोदाहरणों से उभरने वाले स्थापित विधिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, और इसमें एक बहस योग्य कानूनी मुद्दा शामिल है। कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक विपरीत स्थिति में भी उठेगा, जहां विधिक स्थिति स्पष्ट है, या तो विधि के स्पष्ट प्रावधानों या बाध्यकारी उदाहरणों के कारण, लेकिन निचली अदालत ने या तो ऐसे कानूनी सिद्धांत की अनदेखी करते हुए या इसके विपरीत कार्य करते हुए मामले का फैसला किया है। दूसरे प्रकार के मामलों में, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि विधि अभी भी बहस योग्य है, बल्कि इसलिए उठता है क्योंकि किसी भौतिक प्रश्न पर दिया गया निर्णय विधि की स्थापित स्थिति का उल्लंघन करता है।

(iii) सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय निचली

अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यह कोई पूर्ण नियम नहीं है। इसके कुछ सुस्थापित अपवाद हैं जहां (i) निचली अदालतों ने भौतिक सबूतों को नजरअंदाज कर दिया है या बिना किसी सबूत के कार्रवाई की है; (ii) अदालतों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाले हैं; या (iii) अदालतों ने गलत तरीके से साक्ष्य का बोझ डाला है। जब हम "बिना सबूत के निर्णय" का उल्लेख करते हैं, तो यह न केवल उन मामलों को संदर्भित करता है जहां सबूतों की पूरी कमी है, बल्कि ऐसे किसी भी मामले को भी संदर्भित करता है, जहां समग्र रूप से लिया गया साक्ष्य निष्कर्ष का समर्थन करने में उचित रूप से सक्षम नहीं है।"

13. तथ्य की खोज में हस्तक्षेप का दायरा अच्छी तरह से तय है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राजस्थान राज्य बनाम शिव दयाल [(2019) 8 एससीसी 637]*** के हालिया फैसले में चर्चा की है:

"16. जब दूसरी अपील में तथ्य के किसी समवर्ती निष्कर्ष पर सवाल उठाया जाता है, तो अपीलकर्ता को यह इंगित करने का अधिकार है कि यह कानून में अनुचित है क्योंकि इसे दलीलों से अलग दर्ज किया गया था या यह बिना किसी सबूत पर आधारित था या यह सामग्री दस्तावेजी साक्ष्य की गलत व्याख्या पर आधारित था या यह कानून के किसी भी प्रावधान के खिलाफ दर्ज किया गया था और अंत में, यह निर्णय ऐसा है जिस तक न्यायिक रूप से कार्य करने वाला कोई भी न्यायाधीश नहीं पहुंच सका। (विद्वान न्यायाधीश, विवियन बोस, जे. द्वारा की गई टिप्पणी देखें, क्योंकि वह उस समय राजेश्वर विश्वनाथ ममीदवार बनाम दशरथ नारायण चिलवेलकर [एआईआर (1943) नाग 117] पैरा 43) में नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे)।"

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ***कौंडीबा दगडु कदम*** (सुप्रा), ***संतोष हजारी*** (सुप्रा) और ***शिव दयाल*** (सुप्रा) के मामले में बताए गए सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, ***सी डोड्डानारायणन रेड्डी बनाम सी जयारामा रेड्डी [(2020) 4 एससीसी 659***] के मामले में यह कहा कि उच्च न्यायालय के बारे में तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलती करने की बात नहीं कही जा सकती है, जो समवर्ती या उलट हो सकती है, यदि नीचे की अदालत द्वारा निष्कर्ष सामग्री दस्तावेजों की गलत व्याख्या के आधार पर दर्ज किए गए हैं या कानून के किसी भी प्रावधान के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और जहां न्यायिक और उचित रूप से कार्य करने वाला कोई भी न्यायाधीश नहीं ऐसी खोज तक पहुंच सका है।

15. प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्षों में विकृति पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के दायरे और अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, सीपीसी की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अब ध्यान कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर है, जिसका उल्लेख यहां ऊपर किया गया है और जो वर्तमान द्वितीय अपील में विचाराधीन है।

16. ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 21.12.1981 में दर्ज किए गए तथ्य निष्कर्षों और दिनांक 13.05.1988 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री में प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किए गए उलटफेर के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से, एक निर्णय तक पहुंचने के संबंध में प्रथम अपीलीय अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादियों को बेची गई भूमि सार्वजनिक रास्ते/चौक का हिस्सा है, और इसलिए, सिविल मुकदमे पर प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए फैसला सुनाया गया, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.1988 को निर्णय और डिक्री पारित करते समय प्रथम अपीलीय न्यायालय की ओर से निम्नलिखित त्रुटियाँ/विकृतियाँ/अवैधता और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियाँ देखी गईं:

(i) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पीडब्लू-1 (झुंथा राम-वादी संख्या 5) और पीडब्लू-2 (माली राम-वादी संख्या 6) के मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करते हुए पाया कि प्रतिवादियों को आवंटित भूमि सार्वजनिक रास्ते का हिस्सा है

और यदि प्रतिवादियों को अपने संबंधित भूखंडों पर दुकानों का निर्माण करने की अनुमति दी जाती है, तो सार्वजनिक रास्ते की चौड़ाई कम हो जाएगी और संकीर्ण हो जाएगी। प्रथम अपीलीय अदालत ने वादी संख्या 5 और 6 (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) की स्वीकारोक्ति को नजरअंदाज कर दिया, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने गौर किया कि उनके गुआरियों और बाड़ों का मुख्य द्वार/प्रवेश पश्चिमी तरफ से है, न कि मुख्य खाट्टू रींगस रोड के ओर उत्तरी तरफ से जहां ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक भूखंड आवंटित किए गए हैं।

(ii) प्रथम अपीलीय अदालत ने न तो पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार किया, न ही यह माना कि उनके साक्ष्य उनकी मूल शिकायतों के लिए पूरी तरह से विरोधाभासी हैं जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं। वास्तव में, वादी संख्या 5 और 6 की दलीलों से, जैसा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, यह स्पष्ट है कि वस्तुतः उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को भूमि के आवंटन के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत शिकायतों का दावा किया है, अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया है कि भूमि में प्रश्न का उपयोग वे अपने उद्देश्यों के लिए करते हैं। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान सिविल मुकदमे में वादी संख्या 5 और 6 को शामिल करने की पृष्ठभूमि पर सही ढंग से ध्यान दिया है।

(iii) पहली अपीलीय अदालत ने ऐसे सभी तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर ध्यान देना छोड़ दिया है, जो रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि वास्तव में, शुरू में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान मुकदमा वादी संख्या 1 से 4 द्वारा एक ऐसे मामले का दावा करते हुए स्थापित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 सार्वजनिक धर्मशाला के सामने स्थित सार्वजनिक रास्ते/चौक पर अतिक्रमण कर निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। वादी संख्या 1 से 4 तक में से कोई भी वादी इस आशय की दलील को साबित करने के लिए गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुआ है कि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने सार्वजनिक सड़क की चौड़ाई 55 फीट है। बाद में, वादी नंबर 1 केशर देव

ने दिनांक 15.05.1981 को एक आवेदन दायर करके अपना नाम हटाने की मांग करने वाले वर्तमान सिविल मुकदमे से खुद को वापस ले लिया और ट्रायल कोर्ट ने आवेदन की अनुमति दे दी। वादी संख्या 5 और 6, झुंथा राम और माली राम, आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर करके वादी में शामिल हुए। अपने आवेदन में, वादी संख्या 5 और 6 ने कभी भी सार्वजनिक रास्ते के हिस्से के रूप में प्रतिवादियों को आवंटित भूमि का दावा नहीं किया, लेकिन उनका तर्क यह था कि झुंथा राम की ग्वारी का द्वार सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर उत्तरी दिशा की ओर खुलता है, और चौक जहां ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी ने प्रतिवादियों को भूमि आवंटित की और इस भूमि का उपयोग झुंथा राम द्वारा अपने मवेशियों को बांधने के लिए किया जाता है। उन्होंने विवाह, पार्टियों, मृत्यु और दुःख के अवसरों पर भूमि के हिस्से का उपयोग किया। इसी प्रकार, माली राम (वादी नंबर 6) ने तर्क दिया कि उसके नोहरे का मुख्य द्वार उत्तरी दिशा की ओर खुलता है और वह अपने मवेशियों को बांधता है और मवेशी-गाड़ियां लगाता है और साथ ही प्रकाश, हवा और पानी के लिए संबंधित भूमि का उपयोग करता है। आवेदन में तर्क दिया गया कि इस जगह का उपयोग नाग पंचमी के मेले का आयोजन करने के लिए किया जाता है जिसे आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी और झुंथा राम और माली राम को वर्तमान सिविल मुकदमे में वादी संख्या 5 और 6 के रूप में जोड़ा गया था।

(iv) वादी संख्या 5-झुंथा राम और वादी संख्या 6-माली राम ने, वर्तमान सिविल मुकदमे में पक्षकार बनने से पहले, पुनरीक्षण याचिका दायर करके ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में भूमि के आवंटन को अतिरिक्त कलेक्टर/जिला कलेक्टर, सीकर के न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों के पक्ष में जारी पट्टों के विरुद्ध चुनौती दी थी। वादी संख्या 5-झुंथा राम द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका संख्या 50/1975 को आदेश दिनांक 12.03.1976 द्वारा वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया

गया। वादी संख्या 6-माली राम द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका संख्या 13/1976 को जिला कलेक्टर, सीकर की अदालत (प्रदर्श ए 8 और ए 9) द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया

(v) दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.1976 में, यह स्पष्ट रूप से माना गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित भूमि प्रतिवादियों को खुली नीलामी में और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बेची गई थी। संबंधित भूमि को बेचने के लिए सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने से पहले सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। इस प्रकार, प्रतिवादियों के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से ही वैध और उचित माना गया था, इसका अर्थ यह था कि इसे जिला कलेक्टर द्वारा जांच करने और दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद किया गया था। जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.1976 को अंतिम रूप मिल चुका था।

(vi) प्रतिवादियों को प्रश्नगत भूमि का आवंटन स्थायीकरण हेतु किया गया था। वर्तमान सिविल वाद में पुनः चुनौती दी गयी निषेधाज्ञा, पैरा 4(के) को जोड़ने की मांग के माध्यम से और संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति देने के बाद, संशोधित वाद 13.11.1981 को दायर किया गया था, जिसके अनुसार यह तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 7 तक के सार्वजनिक रास्ते के हिस्से को सार्वजनिक भूखंड के रूप में बेच दिया, जो अनुचित, अनधिकृत और अवैध है और ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टे/विक्रय पत्र शून्य हैं। आरंभिक और अप्रभावी. दरअसल, प्रतिवादियों के पक्ष में विचाराधीन भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टों को वादी संख्या 5 और 6 द्वारा चुनौती का निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा अपने दिनांक 20.04.1976 के फैसले में पहले ही कर दिया गया है, और पुनरीक्षण को खारिज करने के बाद वादी संख्या 5 और 6 की याचिकाओं में, उनके साक्ष्य का कोई विश्वसनीय

महत्व नहीं है।

(vii) प्रथम अपीलीय अदालत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वादी ने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से प्रतिवादियों के पक्ष में भूमि के आवंटन और पट्टे जारी करने को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करने के लिए वर्तमान सिविल मुकदमे में घोषणा की राहत की मांग नहीं की है। कारण यह है कि आवंटन पत्र/पट्टे 31.03.1973 को जारी किए गए थे (ए1 से ए7 प्रदर्श) और इन पट्टों को शून्य और शून्य घोषित करने के लिए और 3 साल की सीमा 13.11.1981 को संशोधित वाद पत्र भरने के समय पहले ही समाप्त हो चुकी है, और इससे पहले, वादी संख्या 5 और 6 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाएँ भी क्रमशः 12.03.1976 और 20.04.1976 को खारिज कर दी गई थीं। ट्रायल कोर्ट के अंक संख्या 1 के निष्कर्ष को पलटने से पहले, प्रथम अपीलीय अदालत ने इन भौतिक तथ्यों और सबूतों पर विचार नहीं किया।

(viii) प्रथम अपीलीय अदालत मुद्दे संख्या 1 और 3 के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की सराहना करने में विफल रही। प्रथम अपीलीय अदालत इस तथ्य पर कायम नहीं रह सकी कि वादी संख्या 5 और 6 (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) के साक्ष्य उनके मूलभूत तर्कों के विपरीत हैं। जैसा कि यहां ऊपर प्रकाश डाला गया है। वादी संख्या 5 और 6 ने वस्तुतः प्रतिवादियों को भूमि के आवंटन के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत शिकायतों का दावा करते हुए आरोप लगाया कि विचाराधीन भूमि का उपयोग उनके द्वारा अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसलिए, प्रथम अपीलीय अदालत ने वादी संख्या के मूल तर्कों पर ध्यान दिए बिना, प्रतिवादियों को आवंटित भूमि को सार्वजनिक रास्ते/चौक के हिस्से के रूप में मानने के लिए पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 के साक्ष्य पर भरोसा करने में विकृति की। 5 और 6 और मामले के अन्य पहलुओं पर यहां ऊपर चर्चा की गई है

(ix) प्रथम अपीलीय अदालत ने डीडब्ल्यू-3 बंशीधर, जो कि ग्राम पंचायत,

सीकर का सरपंच है, के पूरे साक्ष्य में से एक पंक्ति के बयान को चुनने में गलती की, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि उसने स्वीकार किया कि प्रतिवादियों को आवंटित भूमि सार्वजनिक रास्ते और चौक का हिस्सा है। डीडबल्यू-3 के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर, यह पता चलता है कि इस तरह की स्वीकारोक्ति स्पष्ट और अस्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने, डीडबल्यू-3 बंशीधर के बयान की समग्र रूप से सराहना करने के बाद, स्पष्ट रूप से माना है कि गवाह (डीडबल्यू-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि सार्वजनिक रास्ते की चौड़ाई 30 फीट है और ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादियों को आवंटित भूमि ग्राम पंचायत की भूमि थी, जो सार्वजनिक रास्ते की भूमि से भिन्न और भिन्न है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भी डीडब्ल्यू-3 की स्वीकृति पर विचार किया, लेकिन वादी और प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों के साथउसके पूरे साक्ष्य को पढ़ने के बाद। दरअसल, डीडब्ल्यू-3 बंशीधर ने कहीं भी स्वीकार नहीं किया कि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने सार्वजनिक रास्ते/चौक की चौड़ाई 55 फीट है, जो कि वाद में वादी का मूल मामला है। इस संदर्भ में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-3 से पीडब्लू-6 के बयानों और डीडब्ल्यू-3 के बयानों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से पाया कि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने स्थित सार्वजनिक रास्ते की चौड़ाई 30 फीट चौड़ी है, जो कि खाटू रींगस रोड है। वादी पक्ष की ओर से यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने, सार्वजनिक रास्ते/चौक की चौड़ाई 55 फीट है। प्रथम अपीलीय अदालत ने गवाह डीडब्ल्यू-3, ग्राम पंचायत के सरपंच के एक पंक्ति के बयान को इस स्वीकारोक्ति के रूप में चुना कि प्रतिवादी नंबर 1 से 7 को किया गया आवंटन सार्वजनिक रास्ते और चौक की भूमि से बाहर है, इस पर विचार नहीं किया गया है। उनके साक्ष्य का दूसरा भाग और अन्य साक्ष्य पीडब्लू-5 उदयनारायण का भी है, जो सार्वजनिक धर्मशाला के प्रबंधक हैं। पीडब्लू-5 स्वीकार करता है कि धर्मशाला के सामने 20 फीट चौड़ी खुली जगह है और उसके बाद खाटू से रींगस तक 30 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क

स्थित है और फिर दक्षिण की ओर ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 से 7 तक आवंटित भूमि है। स्थित है। पीडब्ल्यू-5 स्वीकार करता है कि दस्तावेज़ (प्रदर्श-2) के माध्यम से, सार्वजनिक धर्मशाला के सामने स्थित 20 फीट चौड़ी खुली जगह, ग्राम पंचायत द्वारा धर्मशाला को पहले ही आवंटित की जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी ऐसे आवंटन को चुनौती नहीं दी है (पूर्व-2)। ट्रायल कोर्ट ने इस बिंदु पर ध्यान दिया कि यदि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने सार्वजनिक रास्ते/चौक की चौड़ाई 55 फीट होती, तो सार्वजनिक धर्मशाला के सामने स्थित 20 फीट चौड़े खुले स्थान को धर्मशाला के लिए आवंटित करने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा, वादी के सभी गवाह (पीडब्लू-3, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6) स्वीकार करते हैं कि खाटू-रींगस सार्वजनिक सड़क की चौड़ाई 30 फीट है और पूरे गांव खाटूश्यामजी में 55 फीट चौड़ी कोई सड़क नहीं है बल्कि कहीं-कहीं सड़क की चौड़ाई 30 फीट से भी कम है। जहाँ तक सार्वजनिक धर्मशाला के सामने किसी सार्वजनिक चौक के अस्तित्व का सवाल है, यह किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है और इस आशय का कोई भी साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी मौखिक और दस्तावेजी सबूतों पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने माना कि यह रिकॉर्ड पर साबित नहीं हुआ है कि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने, जघन मार्ग/चौक की चौड़ाई 55 फीट है।

(x) निरीक्षण रिपोर्ट पर भी विचार किया, जिसे केवल डीडब्ल्यू-3 की स्वीकृति के आधार पर प्रथम अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया था। साक्ष्य के कानून का यह मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियाँ नहीं। ट्रायल कोर्ट के दो अलग-अलग पीठासीन अधिकारियों ने ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को सार्वजनिक रास्ते/चौक की भूमि आवंटित करने के आरोप का मुद्दा उठाते हुए, वास्तविक विवाद को स्पष्ट करने के लिए स्वयं स्थल का निरीक्षण करने का फैसला किया। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण के बाद

तैयार किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 29.05.1976 और 09.11.1980 में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 7 को आबंटित प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत छोड़ने के पश्चात 30 फीट चौड़ी खाटू-रींगस रोड दक्षिण दिशा में स्थित है। पीठासीन अधिकारी की यह निरीक्षण रिपोर्ट निर्विवाद है और ट्रायल कोर्ट द्वारा इसे उचित रूप से ध्यान में रखा गया है, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जो साक्ष्य की दृष्टि से स्वीकार्य है। दूसरी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 09.11.1980 भी दूसरे पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के बाद तैयार की गई थी। इस निरीक्षण रिपोर्ट में पुनः तथ्यात्मक पहलू स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक भूमि आवंटन से खाटू से रींगस तक सार्वजनिक सड़क की चौड़ाई एवं उस पर आवागमन अप्रभावित रहता है। दिनांक 09.11.1980 की इस रिपोर्ट पर ट्रायल कोर्ट द्वारा भी विचार किया गया था, जो साक्ष्य का स्वीकार्य अवलोकन है, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया और खारिज कर दिया गया। इसलिए, प्रथम अपीलीय अदालत के दृष्टिकोण को, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, केवल डीडब्ल्यू-3 की स्वीकृति पर भरोसा करने के लिए, वह भी उसके साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़े बिना और रिकॉर्ड पर अन्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए, जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा भी विचार किया गया और उसके बाद स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे को ट्रायल कोर्ट ने इस स्पष्ट तथ्य के साथ खारिज कर दिया कि सार्वजनिक सड़क/चौक का कोई भी हिस्सा ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 से 7 को आवंटित नहीं किया गया है और इसलिए, वादी पक्ष ने प्रतिवादियों के खिलाफ झूठा मामला बनाया है।

(xi) मुद्दे संख्या 1 और 3 के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष सुस्पष्ट और तर्कसंगत हैं, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के ऐसे तथ्य निष्कर्षों को प्रभावित करने और उलटने के लिए बिना कोई कारण

बताए, यह देखा कि खुली भूमि बगल में स्थित है। सार्वजनिक सड़क को सार्वजनिक सड़क के हिस्से के रूप में माना जाएगा, जो डीडब्ल्यू-3 के टुकड़े-टुकड़े विवरण और दस्तावेजों (प्रदर्श 3 और 4) को पढ़ने पर आंशिक रूप से निर्भर करेगा और साथ ही ***फर्म प्यारेलाल सतपाल बनाम संतलाल [डब्ल्यूएलएन (1971)*** भाग I 543] या [एआईआर (1972) राज. 103] के मामले में दिए गए राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा।

(xii) सार्वजनिक रास्ते/चौक की भूमि में से ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 7 को किये गये भूमि आवंटन पर विचार करने वाली प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्ष को अनुमानों और कल्पनाओं के आधार पर पारित कहा जा सकता है। डीडब्ल्यू-3 और दस्तावेजों (एक्स.3 व 4) के साक्ष्य से यह कहीं नहीं पता चलता कि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने 55 फीट चौड़ी सार्वजनिक रास्ता/चौक की जमीन है, जो वर्तमान सिविल मुकदमे में वादी का मूल मामला है। अन्य सभी साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजों, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे नंबर 1 और 3 पर निर्णय लेते समय चर्चा की थी, को प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रथम अपीलीय अदालत ने, डीडब्ल्यू-3 की स्वीकारोक्ति को पूर्ण सत्य माना है, जो स्वयं दस्तावेजों (प्रदर्श ए1 से ए7) के विपरीत है, जो डीडब्ल्यू-3 द्वारा जारी किए गए पट्टे हैं, स्वयं सरपंच और उनकी ऐसी स्वीकृति भी बेमेल है और उसके साक्ष्य के अन्य भाग के अनुरूप नहीं। इसी प्रकार, दस्तावेज़ (उदाहरण 3 और 4), जिनमें से एक वादी संख्या 5 के पक्ष में आवंटन है और दूसरा वादी संख्या 6 के पक्ष में एक उपहार विलेख है, को भी प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा आंशिक रूप से पढ़ा गया है, ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके। एक धारणा यह है कि उनकी गुआरियों के उत्तरी तरफ एक सार्वजनिक रास्ता और चौक स्थित है। प्रथम अपीलीय अदालत ने वादी संख्या 5 और 6 (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) की स्वीकारोक्ति को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनके गुआरियों और बाड़ों का द्वार/प्रवेश द्वार पश्चिमी तरफ से है, न कि

उत्तरी तरफ से, जहां ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक की भूमि को आवंटित किया है। इसके अलावा, जब ट्रायल कोर्ट ने इन सभी मौखिक बयानों और दस्तावेजों की सराहना की है और उन पर चर्चा की है, तो पहले से इसकी उम्मीद नहीं है, अतः अपीलीय अदालत ने रिकॉर्ड से टुकड़ों में साक्ष्य और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सभी साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को चुनकर पलट दिया। जब ट्रायल कोर्ट ने सभी सबूतों पर विचार किया है, जब तक कि उन्हें अस्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तब तक पहली अपीलीय अदालत उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी या उसे खारिज नहीं कर सकती थी। कानून के प्रस्ताव के अनुसार, प्रथम अपीलीय अदालत को, प्रतिवादी नंबर 1 से 7 को आवंटित भूमि को सार्वजनिक सड़क और चौक के रूप में मानने के बारे में अपना निष्कर्ष या धारणा निकालने से पहले, तथ्य को उलटने और परेशान करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता थी। ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष. प्रथम अपीलीय अदालत का निर्णय इस पहलू पर मौन है और इस प्रकार ***संतोष हजारी*** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव के विपरीत और असुरक्षित है।

(xiii) जहां तक **फर्म प्यारेलाल सतपाल** (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले का सवाल है, जिस पर प्रथम अपीलीय अदालत ने भरोसा जताया है, कानून का सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। उस मामले में, विचाराधीन मुद्दा गंगापुर टाउन के धानमंडी क्षेत्र में सार्वजनिक और राजमार्ग सड़क के किनारे 50 फीट की चौड़ाई वाली भूमि के कुछ हिस्से का आवंटन था। इस न्यायालय की एकल पीठ का **म्यूनिसिपल बोर्ड, मंगलौर बनाम महादेवजी महाराज** ***[एआईआर (1965) एससी 1147]*** के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए यह मानना था कि स्थल की भूमि को आम तौर पर सड़क में शामिल किया जाता है, क्योंकि वे सड़क के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक हैं।

जबकि वर्तमान मामले में, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान सिविल मुकदमे के माध्यम से, वादी ने केवल सार्वजनिक धर्मशाला के सामने, 55 फीट तक सड़क की चौड़ाई का दावा किया है खाटू-रींगस की पूरी सड़क का नहीं। निर्विवाद रूप से खाटू-रींगस रोड की चौड़ाई 30 फीट है। धर्मशाला के सामने स्थित 20 फीट खुली जगह पहले ही धर्मशाला को आवंटित की जा चुकी है। इसके बाद खाटू-रींगस की 30 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क उपलब्ध है और फिर दक्षिणी दिशा की ओर संबंधित भूमि स्थित है। वास्तव में, यह एक ऐसा मामला है जहां सार्वजनिक सड़क की 30 फीट की चौड़ाई सवाल में नहीं है, बल्कि वादी सार्वजनिक धर्मशाला के सामने एक सार्वजनिक चौक का दावा कर रहे हैं। रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, सार्वजनिक रास्ते/चौक का अस्तित्व कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है। खाटू-रींगस से धर्मशाला तक सार्वजनिक सड़क के उत्तरी किनारे पर 20 फीट चौड़ी खुली जगह का आवंटन विवाद में नहीं है, जैसा कि दस्तावेज़ (प्रदर्श-2) से स्पष्ट है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, धर्मशाला के सामने 20 फीट चौड़ी खुली जगह छोड़ने और फिर 30 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क छोड़ने के बाद मुख्य सार्वजनिक सड़क के दक्षिण की ओर स्थित खुली भूमि को अनुपात लागू करके सार्वजनिक सड़क का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। **फर्म प्यारेलाल सतपाल** (सुप्रा) के मामले में प्रतिपादित कानून के अनुसार प्रथम अपीलीय अदालत ने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना, उस कानून को वर्तमान मामले में लागू करने में अवैधता और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है और गलत धारणा बनाई है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 से 7 को आवंटित भूमि खाटू-रींगस की सार्वजनिक सड़क का हिस्सा माना जाए।

17. इस न्यायालय ने पाया कि प्रथम अपीलीय अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध ठोस सबूतों पर भरोसा करने के बजाय अनुमानों और कल्पनाओं के आधार पर तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज किया है और इन्हीं पर ट्रायल कोर्ट ने विचार किया और

आगे सबूतों के स्वीकार्य कथनों को नजरअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलटने/प्रभावित करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, जिन्हें रिकॉर्ड पर पूरे सबूतों पर विचार करने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया था। इस दृष्टि से, प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्ष, मुद्दे संख्या 1 और 3 के निष्कर्षों को उलटते हुए, ये विकृत और कानून के स्थापित प्रस्ताव के विपरीत माने जा सकते हैं।

18. प्रथम अपीलीय अदालत ने दलीलों और साक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया है कि यह वादी का स्वीकृत मामला है कि धर्मशाला के सामने 20 फीट चौड़ा खुला स्थान है और फिर खाटू रींगस से दांतारामगढ़ तक सार्वजनिक मार्ग के लिए 30 फीट की सड़क स्थित है। धर्मशाला के सामने स्थित 20 फीट चौड़ी खुली जगह पहले से ही ग्राम पंचायत द्वारा धर्मशाला के पक्ष में आवंटित की जा चुकी है, जो कि प्रदर्श-2, आवंटन दिनांक 20.10.1968 से साबित होती है, इस आवंटन के माध्यम से 20X125 फीट खुली जगह सार्वजनिक धर्मशाला को आवंटित की गई थी और पीडब्लू-5 उदयनारायण, जो सार्वजनिक धर्मशाला के प्रबंधक हैं, भी यही स्वीकार करते हैं। इस आवंटन को कभी चुनौती नहीं दी गई। ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 30 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते के अलावा कोई सार्वजनिक रास्ता/चौक था, तो इसका कोई कारण नहीं है कि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने स्थित यह खुला स्थान ग्राम पंचायत और उसी द्वारा कैसे और क्यों आवंटित किया गया था। वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। ट्रायल कोर्ट के ऐसे सबूतों और निष्कर्षों के बावजूद, प्रथम अपीलीय अदालत ने हालांकि यह स्वीकार किया कि सार्वजनिक रास्ते की चौड़ाई 30 फीट है, तथापि, यह माना कि धर्मशाला के सामने, सार्वजनिक सड़क और चौक की चौड़ाई 55 फीट है और प्रथम अपीलीय की ऐसी टिप्पणियाँ अदालत रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के बिल्कुल विपरीत है और केवल कल्पनाओं पर आधारित हैं।

19. प्रथम अपीलीय अदालत ने दस्तावेजों, प्रदर्श-3, वादी संख्या 5-झुंथा राम के पक्ष में आवंटन और प्रदर्श-4, वादी संख्या 6 माली राम के पक्ष में उपहार विलेख पर भरोसा रखा। इन दस्तावेज़ों में यद्यपि उत्तरी दिशा की ओर सार्वजनिक

रास्ता होने का उल्लेख है, तथापि ट्रायल कोर्ट ने देखा कि प्रदर्श-3 में ही यह संकेत दिया गया है कि इस भूमि पर प्रवेश के लिए मुख्य द्वार पश्चिमी दिशा से होगा। इसके अलावा, वादी संख्या 5 और 6 ने, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के रूप में उपस्थित होते हुए, अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उनके ग्वारियों का मुख्य द्वार/प्रवेश द्वार पश्चिमी तरफ से है, न कि उत्तरी तरफ से मुख्य खाटू रींगस रोड की ओर। प्रथम अपीलीय अदालत ने, ट्रायल कोर्ट के ऐसे निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण बताए बिना, वादी नंबर 5 और 6 की गुआरियों का प्रवेश खाटू रींगस की मुख्य सड़क से उत्तरी दिशा की ओर माना है, जो पूरी तरह से विकृत है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी संख्या 5 और 6 के बयानों के साथ-साथ स्वयं पीठासीन अधिकारियों की साइट निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेज़ प्रदर्श-2 और 4 का अवलोकन किया है और देखा है कि वादी संख्या 5 एवं 6 के गुआरिस और बाडा के प्रवेश/द्वार पश्चिमी दिशा से है, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को संबंधित भूमि के आवंटन पर बिल्कुल भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि इन भूमियों का प्रवेश खाटू की मुख्य सड़क के उत्तरी दिशा मे रींगस की ओर खुल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने देखा कि वादी द्वारा वादी प्रदर्श-1 के साथ संलग्न नक्शा, साइट मैप के अनुसार पूरी तरह से गलत है, जैसा कि पीठासीन अधिकारी ने अपनी साइट निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.05.1976 में साइट के निरीक्षण के बाद तैयार किया था। प्रतिवादियों को आवंटित भूमि 30 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते को छोड़कर सार्वजनिक मार्ग के दक्षिणी स्थल पर स्थित पाई गई और उसके बाद ग्वारी और झूंथा राम के मकान मिले। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने, समग्र रूप से साक्ष्य के अवलोकन के बाद, निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन भूमि 30 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते का हिस्सा नहीं है और वहां कोई सार्वजनिक चौक नहीं है और इसके अलावा वादी संख्या 5 और 6 की ग्वारियां और बाड़े हैं। इस भूमि की ओर कोई रास्ता नहीं है तथा ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का आवंटन सार्वजनिक रास्ते या चौक की भूमि से बाहर नहीं है। मुद्दे क्रमांक 1 और 3 के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों का अवलोकन स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर साक्ष्य के प्रत्येक और पूरे टुकड़े की सराहना दिखाते हैं, लेकिन पहली अपीलीय अदालत ने, उस सबूत पर ध्यान दिए

बिना और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों के करीब आए बिना, केवल दस्तावेज़ों (प्रदर्श-3 और 4) पर आंशिक रूप से भरोसा करते हुए, संपूर्ण रूप से नहीं, मान्यताओं के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालकर ऐसे तथ्य निष्कर्षों को उलट दिया है। इसलिए, सार्वजनिक रास्ते और चौक के हिस्से के रूप में प्रतिवादियों को आवंटित भूमि के संबंध में प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्ष और टिप्पणियां विकृत हैं।

20. प्रथम अपीलीय अदालत ने यह अनुमान लगाते हुए कि ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को पट्टों (प्रदर्शनी ए 1 से ए 7) के माध्यम से भूमि का आवंटन सार्वजनिक रास्ते/चौक का हिस्सा है, यह देखा कि हालांकि, ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया और नियमों और कानून की प्रक्रिया का पालन किया, फिर भी, ग्राम पंचायत सार्वजनिक रास्ते की भूमि की बिक्री/सार्वजनिक नीलामी के लिए अधिकृत नहीं थी। यह देखा जा सकता है कि प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्षों से पता चलता है कि ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पक्ष में भूमि का आवंटन किया, जो सार्वजनिक रास्ते/चौक का हिस्सा है। बिना किसी सबूत के और पूरी तरह से आधारित होने के कारण यह धारणाएँ और अनुमान. अपने आप में विकृत है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टे अपने आप में अमान्य नहीं माने जा सकते थे, विशेष रूप से तब जब यह पाया गया हो कि ये पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया नियमों का पालन करने के बाद जारी किए गए थे। प्रथम अपीलीय अदालत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वादी कहीं भी प्रतिवादियों के इन आवंटन/पट्टों को शून्य घोषित करने की घोषणा नहीं मांगते हैं। रिकॉर्ड पर यह निर्विवाद स्थिति है कि वादी क्रमांक 1 को 4 अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित नहीं हुए कि प्रतिवादियों को आवंटित भूमि सार्वजनिक रास्ते का हिस्सा है और अतिरिक्त कलेक्टर, सीकर के समक्ष वादी संख्या 5 द्वारा पट्टों को दी गई चुनौती को पहले ही निर्णय दिनांक 12.03.1976 के तहत वापस ले लिया गया है (प्रदर्श-ए8) खारिज कर दिया गया है।). और वादी संख्या 6 द्वारा पट्टों को चुनौती, जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 20.04.1976 (प्रदर्श-ए7) द्वारा गुण-दोष के

आधार पर खारिज कर दी गई है। इन पट्टों की वैधता को सिविल कोर्ट में चुनौती देने की सीमा तीन साल है जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। संशोधित वादपत्र में, इन पट्टों को आरंभिक रूप से शून्य और अप्रभावी बताते हुए चुनौती देते हुए, वादी ने कहीं भी इन पट्टों के संबंध में संशोधित वादपत्र में घोषणात्मक राहत की मांग नहीं की। [जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.1976 (प्रदर्शन ए7) में स्पष्ट रूप से माना है कि ये पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जारी किए गए थे और भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को सार्वजनिक रूप नीलामी से बेची गई थी।] प्रथम अपीलीय अदालत भी जिला कलेक्टर के ऐसे निष्कर्षों और प्रक्रिया निष्कर्षों से सहमत थी और पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पट्टे जारी किए गए हैं। ऐसे परिदृश्य में, जहां प्रश्नगत भूमि को सार्वजनिक मार्ग/चौक का भाग नहीं माना जा सकता, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन को इस आशय की घोषणात्मक राहत की मांग किए बिना शून्य और अप्रभावी नहीं माना जाना चाहिए।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अंबेडकर [(2020) 7 एससीसी 725]*** के मामले में अपने हालिया फैसले में यह माना कि राज्य अधिकारियों द्वारा राज्य भूमि के आवंटन के नीलामी/आदेशों को अवैध घोषित करने के लिए किसी घोषणात्मक राहत के बिना, केवल निषेधाज्ञा के लिए एक सरल नागरिक मुकदमा, सुनवाई योग्य नहीं है। उस मामले में वादी ने प्रतिनिधि क्षमता में प्रतिवादियों और राज्य सरकार के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि रत्नागिरी नगर परिषद मुकदमे की संपत्ति में एक ठोस अपशिष्ट निपटान परियोजना स्थापित करने का इरादा रखता है, जो गांवों के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करेगा। चूंकि इससे गंभीर जल प्रदूषण होने की अपार संभावना है और आगे प्रतिवादियों ने सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली थी, इसलिए, परियोजना स्थापित न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई थी। हालाँकि, प्रतिवादी और राज्य सरकार ने लिखित बयान में कहा कि

विशेषज्ञ समिति के साथ उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद प्रतिवादी को वाद भूमि आवंटित की गई थी, और परियोजना स्थापित करने के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाद भूमि आवंटित करने और प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि पर परियोजना स्थापित करने की अनुमति देने के इस तरह के खुलासे के बावजूद, वादी ने न तो सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की आलोचना की और न ही उस संबंध में किसी घोषणात्मक राहत के लिए प्रार्थना की। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आदेशों के अंकित मूल्य पर प्रतिवादी को वाद भूमि का आबंटन तथा आदेश देने के संबंध में प्रतिवादी को वाद भूमि पर ठोस जल निपटान परियोजना स्थापित करने की अनुमति दी गई, यह देखा गया और माना गया कि वादी ने ऐसे आदेश की अमान्यता के बारे में घोषणा की मांग नहीं की है और न ही ऐसे आदेशों को प्रभावित किया है और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए उसका सरल वाद सुनवाई योग्य नहीं है।

22. **रत्नागिरी नगर परिषद** (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कृष्णादेवी मालचंद कामथिया बनाम बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप [(2011) 03 एससीसी 363]*** के मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इस अदालत ने निम्नानुसार देखा:-

> "इस प्रकार, उपरोक्त से यह पता चलता है कि भले ही आदेश/अधिसूचना अमान्य/निरस्त करने योग्य हो, लेकिन उससे व्यथित पक्ष यह निर्णय नहीं ले सकता कि उक्त आदेश/अधिसूचना उस पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसी घोषणा के लिए उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। आदेश काल्पनिक रूप से अमान्य हो सकता है और भले ही किसी दिए गए परिस्थिति में इसकी अमान्यता को अदालत के समक्ष चुनौती दी गई हो, अदालत याचिकाकर्ता की स्थिति या देरी के आधार पर या सिद्धांत सहित विभिन्न आधारों पर इसे रद्द करने से इनकार कर सकती है। छूट या कोई अन्य कानूनी कारण। आदेश एक उद्देश्य या एक व्यक्ति के लिए अमान्य हो सकता है,

> किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हो सकता है।"

रत्नागिरी नगर परिषद (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***स्मिथ बनाम पूर्वी एलो ग्रामीण जिला परिषद [(1956) एसी 736***] के मामले में पिछले प्रसिद्ध फैसले पर भी भरोसा किया। और निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

> "कोई आदेश, भले ही अच्छे विश्वास में नहीं दिया गया हो, फिर भी कानूनी परिणामों के लिए सक्षम एक कार्य है। इसके माथे पर अशक्तता का कोई चिह्न नहीं है। जब तक अमान्यता का कारण स्थापित करने और इसे रद्द करने या अन्यथा परेशान करने के लिए कानून में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है, तब तक यह अपने प्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए सबसे त्रुटिहीन आदेशों के समान ही प्रभावी रहेगा।

23. इसलिए, प्रथम अपीलीय अदालत ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सरल नागरिक मुकदमे को डिक्री करने और प्रश्नगत भूमि के संबंध में इसे प्रतिवादियों के खिलाफ मानने में विकृति और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की, जिसे ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादियों को, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है और वादी द्वारा दायर सिविल मुकदमे में इन आवंटनों को शून्य घोषित करने के लिए कोई घोषणात्मक राहत की प्रार्थना नहीं की गई थी। उस दृष्टि से, प्रथम अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 13.05.1988 अवैध और विकृत है।

24. उपरोक्त वर्णित अवैधताओं और विकृतियों के अलावा, प्रथम अपीलीय अदालत के आक्षेपित फैसले के पैरा 7 की निचली पंक्तियों के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अपीलीय अदालत ने ग्राम खाटूश्यामजी में जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया, उससे कई तीर्थयात्रियों का आना-जाना लगा रहता है तथा धार्मिक मेले का आयोजन भी बार-बार होता रहता है, अतः सार्वजनिक धर्मशाला के सामने स्थित भूमि को खुला रखना उचित एवं युक्तिसंगत

होगा। इस तरह के निष्कर्ष मनमाने हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद दलीलों और सबूतों के विपरीत हैं। वादीगण पर यह भार था कि वह साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करे कि सार्वजनिक धर्मशाला के सामने सड़क एवं चौक की चौड़ाई 55 फीट है, जिसे सिद्ध नहीं किया गया तथा इसके विपरीत ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि का आवंटन कर दिया गया। नंबर 1 से 7, 30 फीट सार्वजनिक सड़क छोड़ने के बाद, साबित हो गया है और प्रतिवादी नंबर 1 से 7 को जारी किए गए पट्टे, जिन्हें वर्तमान सिविल मुकदमे में चुनौती नहीं दी गई थी, को इस आधार पर शुरू से ही मनमाने निष्कर्ष और शून्य तर्क नहीं माना जा सकता था। इस संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष भी उपयुक्त हैं विकृत और अस्थिर हैं।

25. यहां ऊपर की गई चर्चाओं के बाद, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय सकारात्मक और अपीलकर्ताओं के पक्ष में किया जाता है।

26. ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं को बेची/आवंटित की गई भूमि सार्वजनिक रास्ते/चौक का हिस्सा है, इस निष्कर्ष को दर्ज करने में प्रथम अपीलीय अदालत की ओर से विकृति को ध्यान में रखते हुए, यह पता चलता है कि ऐसे निष्कर्ष हैं जो बिना किसी साक्ष्य के आधार पर हैं और पहली अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यान नहीं दिया और न ही ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलटने के लिए कारण बताए, इसके अलावा पहली अपीलीय अदालत ने रिकॉर्ड पर सामग्री और प्रासंगिक सबूतों पर विचार नहीं किया है, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने विचार किया था। ***कोंडीबा दगडु कदम*** **(सुप्रा)** और **संतोष हजारी (सुप्रा)** के मामले में प्रतिपादित कानून का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्य पर लागू होता है और आगे माननीय द्वारा अनुमति के अनुसार नीचे की अदालतों के तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप के दायरे के अनुसार लागू होता है। ***सेबेस्टियाओ लुइस फर्नांडीस*** (सुप्रा) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.05.1988 के आक्षेपित फैसले और डिक्री में सीपीसी की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कहा था कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रथम

अपीलीय अदालत के निष्कर्ष अनुमानों और अनुमानों पर आधारित हैं और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की गलत व्याख्या से भी ग्रस्त हैं, इसलिए, ***शिव दयाल*** (सुप्रा) के मामले में और मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार ***सी डोड्डानारायण रेड्डी*** (सुप्रा) की बात भी लागू होती है।

27. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि इस ओर से बताई गई विकृति और अवैधताओं के अनुसार वादी के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए प्रथम अपीलीय अदालत का प्रतिवादियों को इस धारणा के आधार पर कि दिया गया निर्णय कि प्रतिवादियों को आवंटित भूमि सार्वजनिक रास्ते/चौक का हिस्सा है, कानून की दृष्टि से अस्थिर है और रद्द किए जाने योग्य है।

28. परिणामस्वरूप, तत्काल दूसरी अपील की अनुमति दी जाती है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीकर की अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 13.05.1988 को रद्द कर दिया गया है। न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 21.12.1981 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार, उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

29. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

30. अन्य सभी आवेदनों (यदि कोई हों) का भी निपटारा कर दिया गया है।

31. निचली अदालतों के रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजे जाएं।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

SACHIN

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।